

## **प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना**

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई), पहले इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक सामाजिक कल्याण प्रमुख कार्यक्रम है। [१] शहरी गरीबों के लिए इसी तरह की योजना 2015 में 2022 तक सभी के लिए आवास के रूप में शुरू की गई थी। इंदिरा आवास योजना 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी, जिसके निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। गांवों में बीपीएल आबादी के लिए मकान। [२] २०१ ९

### **लाभ**

1. हर नागरिक के लिए बड़ी सब्सिडी

पीएमएवाई योजना का सबसे बड़ा लाभ नए घर खरीद पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है। हालाँकि, अपनी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आप या आपके घर में कोई भी पहले से ही एक गृहस्वामी नहीं हो सकता है। सरकार ईडब्ल्यूएस / एलआईजी से लेकर एमआईजी 1 और एमआईजी 2 तक आपकी आय के आधार पर क्रेडिट लिंकड सब्सिडी प्रदान करती है।

- जो लोग ईडब्ल्यूएस / एलआईजी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए होम लोन की ब्याज दरों में 20 साल के कार्यकाल के लिए 6.5% की सब्सिडी दी जाती है।
- जो लोग मिड-लेवल एमआईजी श्रेणी में आते हैं, उनके लिए होम लोन की ब्याज दर 20 साल के कार्यकाल के लिए अधिकतम 9 लाख रुपये की ऋण राशि पर 4% की सब्सिडी है।
- जो लोग एमआईजी 2 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए गृह ऋण ब्याज दर 20 वर्ष के कार्यकाल के लिए 12 लाख रुपये की अधिकतम मूल राशि पर 3% की सब्सिडी है।

## 2. समाज के सभी क्षेत्रों के लिए आवास

पीएमएवाई योजना के तहत, सरकार उन लोगों के लिए प्रमुख शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ किफायती घरों का निर्माण करना चाहती है जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इन घरों का निर्माण महाराष्ट्र, पश्चिम जैसे राज्यों में शुरू हो चुका है

बंगाल, तमिलनाडु, आदि इन घरों के माध्यम से, सरकार कई लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सक्षम होगी।

## 3. देश के हर कोने में आवास विकास

PMAY योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है; निम्न-मध्यम और मध्यम आय वर्ग के ग्रामीण विकास को भी समान महत्व दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में, निम्न-आय वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर को बढ़ाने के अलावा,

प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा शुरू की गई योजनाएं ग्रामीण अचल संपत्ति क्षेत्र और संबंधित उद्योगों में विकास की गारंटी देती हैं।

#### 4. महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए लाभ

PMAY महिला होमशिप को एक अनिवार्य खंड बनाता है और उल्लेख करता है कि घर को एक महिला के नाम पर तब भी पंजीकृत होना चाहिए जब वह संपत्ति नहीं खरीद रही हो। इसके अतिरिक्त, वेतनभोगी महिलाओं, विधवाओं, ट्रांसजेंडर लोगों, विकलांगों, अल्पसंख्यकों और वरिष्ठों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ उठाने और घर के मालिक बनने के लिए वरीयता प्रावधान मौजूद हैं। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में इस योजना के तहत घर खरीदते हैं, तो आपको भूतल पर रहने का आश्वासन दिया जा सकता है क्योंकि इस योजना ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य खंड के रूप में जोड़ा है।

#### 5. पर्यावरण के अनुकूल घरों से लाभ

डेवलपर्स को इस योजना के तहत पर्यावरण के अनुकूल निर्माण तकनीक और सामग्रियों का उपयोग करके घर बनाने का निर्देश दिया गया है। यह निर्माण स्थलों पर और इसके आस-पास के वातावरण पर सीमित क्षति सुनिश्चित करेगा और प्रदूषण की मात्रा को भी कम रखेगा।

## पात्रतामापदंड

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति गैर-अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जनजाति के बीपीएल ग्रामीण परिवार।

पुनर्वासित और पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों सहित मैनुअल मैला ढोने वालों के परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके

बाद होने वाली प्राथमिकता इस प्रकार है: - i। मुश्किल

परिस्थितियों में महिलाएँ, जिनमें विधवाएँ, तलाकशुदा या निर्जन, अत्याचार की शिकार महिलाएँ और जिनके पति कम

से कम तीन साल से लापता हैं, और, महिलाएँ परिवारों का

नेतृत्व कर रही हैं। ii। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति

(कम से कम 40% विकलांगता के साथ) iii। शारीरिक रूप से

विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40% विकलांगता के साथ)

iv। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों v। विधवाओं और रक्षा / अर्धसैनिक /

पुलिस बलों के सदस्यों के अगले-के-परिचारक कार्रवाई में मारे

गए (भले ही BPL नहीं) vi। अन्य आवासहीन बीपीएल परिवार

1. लाभार्थी परिवार के पास अपने नाम से या उसके नाम पर

या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के

किसी भी हिस्से में पक्के घर (एक सभी मौसम में रहने वाली

इकाई) नहीं होने चाहिए।

2. लाभार्थी परिवार को भारत सरकार / राज्य सरकार की

किसी भी आवासीय योजना के तहत केंद्रीय सहायता का लाभ

नहीं उठाना चाहिए।

3. लाभार्थी परिवार को किसी भी पीएमएवाई - सीएलएसएस सब्सिडी का लाभ किसी प्राथमिक ऋण संस्थान (। पीएलआई ' ) से नहीं लेना चाहिए।

4. बैलेंस ट्रांसफर के मामले में, मौजूदा ऋणदाता से ट्रांसफर करने का इरादा रखने वाले मूल गृह ऋण को MIG श्रेणी के लिए 01 जनवरी 2017 के बाद और EWS / LIG श्रेणी के लिए 17 जून 2015 को लिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, लाभार्थी परिवार को मौजूदा ऋणदाता से PMAY सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहिए।

5. जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक नगर और बाद में अधिसूचित शहर मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

6. निर्माण / विस्तार जिसके लिए ऋण लिया जाता है उसे ऋण राशि की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

## आवेदन कैसे करें

- ऑनलाइन:

प्रधान मंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन आवेदन करना संभव है। के लिए लागू लाभ के प्रकार के आधार पर, विभिन्न रूप हैं जिन्हें भरना होता है। फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम का लाभ लेने वाले लाभार्थी सीधे ऋण प्राप्त बैंकों से संपर्क कर सकते हैं जो होम लोन प्रदान करते हैं। सब्सिडी का भुगतान सीधे बैंक को किया जाएगा और उधारकर्ता के लिए ऋण की बकाया राशि को कम किया जाएगा।

- [pmaymis.gov.in](http://pmaymis.gov.in)

- ऑफ़लाइन:

उन लोगों के लिए जो पीएम आवास योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं, यह राज्य सरकारों द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में एक फॉर्म भरकर संभव है। ऑफ़लाइन फॉर्म रुपये के लिए भरे जा सकते हैं। 25 से अधिक जी.एस.टी. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी निजी व्यक्ति या कंपनियों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धन इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।

## **दस्तावेजों की जरूरत है**

- पहचान प्रमाण

पैन कार्ड (अनिवार्य) और नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक

1. वोटर कार्ड
2. आधार कार्ड
3. वैध पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. फोटो क्रेडिट कार्ड
6. सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र। तन
7. मान्यताप्राप्त लोक प्राधिकारी या लोक सेवक का पत्र जो फोटोग्राफ के साथ ग्राहक की पहचान की पुष्टि करता है (30 दिन से अधिक पुराना नहीं)

- पते का सबूत

नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक:

1. वोटर कार्ड
2. आधार कार्ड
3. वैध पासपोर्ट
4. ग्राहक की पहचान और निवास की पुष्टि करने वाले किसी मान्यताप्राप्त लोक प्राधिकरण या लोक सेवक का पत्र
5. नवीनतम उपयोगिता बिल
6. स्टाम्प पेपर पर किराया समझौता
7. किसी भी वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक के उधारकर्ताओं के पते को दर्शाने वाले बैंक विवरण
8. क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट 3 महीने से अधिक पुराना नहीं है
9. जीवन बीमा पॉलिसी

10. कंपनी लेटरहेड पर नियोक्ता द्वारा निवास का पता प्रमाण पत्र / पत्र
  11. यदि स्वामित्व में है तो संपत्ति (बिक्री) के विक्रय विलेख की प्रति
  12. नगरपालिका या संपत्ति कर रसीद
  13. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
  14. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)। विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यदि उनका पता है
  15. राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र। विभाग, वैधानिक या विनियामक निकाय, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संस्थान और सूचीबद्ध कंपनियाँ। इसी तरह, ऐसे नियोक्ताओं के साथ छुट्टी और लाइसेंस समझौते जो आधिकारिक आवास आवंटित करते हैं
  16. सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़। विदेशी अधिकार क्षेत्र और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र
    - आय का प्रमाण
- नीचे दिए गए सभी दस्तावेज़:
1. पिछले 2 महीने की वेतन पर्ची
  2. पिछले 6 महीने के वेतनभोगी खाते का बैंक स्टेटमेंट
  3. नवीनतम फॉर्म 16 / आईटीआर



- अन्य दस्तावेज 6 महीने के चुकौती बैंक के बयानों के साथ-साथ चल रहे ऋण से संबंधित दस्तावेज
- संपत्ति के दस्तावेज

नीचे दिए गए सभी दस्तावेज:

1. संपत्ति के पूर्ण श्रृंखला दस्तावेजों की प्रतिलिपि (जैसा कि लागू हो)
2. बेचने के लिए समझौते की प्रति (यदि निष्पादित हो)
3. आबंटन पत्र / क्रेता समझौते की प्रति (यदि लागू हो)
4. डेवलपर को किए गए भुगतान / भुगतानों की रसीद / प्रतियों की प्रति (यदि लागू हो)

## **किसीभीप्रश्नकेलिए**

वेबसाइट: <https://pmayg.nic.in/netiay/FAQ.aspx>

टोल फ्री नं: 1800-11-6446